Part V: The Union

Part V of the Constitution of India deals with the Union and its territories. It contains provisions regarding the territorial extent of the Union of India, the territories of the States, and the territories of the Union territories.

Article 1 of this part defines the territory of India to include the territories of the States and the Union Territories, and provides for the Parliament's power to alter the territories of the States and the Union Territories.

Articles 2 to 4 deal with the admission or establishment of new States and the alteration of boundaries of existing States.

Articles 245 to 255 deal with the distribution of legislative powers between the Union and the States. The Union Parliament has exclusive powers to make laws on certain subjects enumerated in the Union List, while the State Legislatures have the power to make laws on subjects enumerated in the State List. In case of a conflict between the Union and State laws, the Union law prevails.

Article 256 provides for the obligation of States to comply with the laws made by Parliament and the executive power of the Union to extend to the administration of the States.

Overall, Part V of the Constitution of India defines the territorial extent of the Union of India, and lays down the powers and responsibilities of the Union and the States in relation to the governance of the territories.

भाग V: संघ

भारत के संविधान का भाग V संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें भारत संघ की क्षेत्रीय सीमा, राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र के संबंध में प्रावधान हैं।

इस भाग का अनुच्छेद 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को बदलने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 2 से 4 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है।

अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। केंद्रीय संसद के पास संघ सूची में शामिल कुछ विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं, जबकि राज्य विधानमंडलों के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। संघ और राज्य के कानूनों के बीच विरोध के मामले में, संघ कानून प्रबल होता है।

अनुच्छेद 256 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए राज्यों के दायित्व और राज्यों के प्रशासन तक विस्तार करने के लिए संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग V भारत संघ की क्षेत्रीय सीमा को परिभाषित करता है, और प्रदेशों के शासन के संबंध में संघ और राज्यों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।